

तटीय सुरक्षा स्कीम

भारत का समुद्र तट

भारत का समुद्र तट 7516.6 किमी लम्बा है जो मुख्य भूमि और द्वीपों की तटवर्ती सीमा है और गुजरात (1214.70 किमी), महाराष्ट्र (652.60 किमी), गोआ (101.00 किमी), कर्नाटक (208.00 किमी), केरल (569.70 किमी), तमिलनाडु (906.90 किमी), आंध्र प्रदेश (973.70 किमी), उड़ीसा (476.70 किमी) और पश्चिम बंगाल (157.50 किमी) और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव (42.50), लक्षदीप (132.00), पुडुचेरी (47.60 किमी) और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (1962.00 किमी) से गुजरती है।

वर्तमान तटीय सुरक्षा व्यवस्था

आईएन को समग्र समुद्री सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तमरदायी प्राधिकारी नामोदिष्ट किया गया है जिसमें तटवर्ती सुरक्षा तथा अपतटवर्ती सुरक्षा भी शामिल है। आईएन की सहायता के लिए भारतीय सुरक्षा गार्ड (आईसीजी), राज्य तटीय पुलिस तथा अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियां हैं।

आईसीजी तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाये जाने वाले क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय समुद्र जल में तटवर्ती सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी है। डीजी, आईसीजी को कमांडर तटीय कमांड के रूप में नामोदिष्ट किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे।

तटीय सुरक्षा स्कीम – सिंहावलोकन

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन चरणों में कर रहा है और इसका उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के नजदीक उथले क्षेत्रों की गश्त और निगरानी के लिए तटीय पुलिस की अवसररचना तथा क्षमताओं को मजबूत बनाना है।

तटीय सुरक्षा स्कीम (चरण-1) :

तटीय सुरक्षा स्कीम (चरण-1) का कार्यान्वयन 2005 से 2011 तक किया गया था। स्कीम के अधीन तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यस क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस थाने (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट्स, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नाव, 153 जीपें और 312 मोटर साइकिलें मुहैया करायी गयी थीं।

तटीय सुरक्षा स्कीम (चरण-2) :

स्की म के चरण-2 के अधीन तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य0 क्षेत्रों को 131 सीपीएस, 60 जेट्टी, 10 मेरिन ऑपरेशन सेंटर, 225 नावें, 131 चौपहिए वाहन और 242 मोटर साईकिले मंजूर की गयी हैं। इस स्कीटम का चरण-2, 31.03.2020 तक कार्यान्वयन के अधीन रहेगा।

तटीय सुरक्षा स्कीरमें

तटीय सुरक्षा स्कीरम चरण-1

73 तटीय पुलिस स्टेशनों (सीपीएस), 97 जांच चौकियों, 58 आउटपोस्टों, 30 बैरकों, 204 नावों, 153 जीपों और 312 मोटर साइकिलों के साथ यह चरण मार्च, 2011 में पूर्ण कर लिया गया है।

तटीय सुरक्षा स्कीम (चरण-2)

स्की म में समुद्री गश्त(के लिए तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्ति अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करके और भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल, आदि द्वारा की जा रही अन्यम तटीय सुरक्षा पहलों की सहायता की दृष्टि से तटीय सुरक्षा चरण-1 स्कीम में निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया है। तटीय सुरक्षा चरण-2 स्कीम को 1579.91 करोड़ रुपये के परिव्यय से दिनांक 01.04.2011 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए मंजूर किया गया है। इस स्की म की कार्य अवधि दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2020 तक के लिए बढ़ायी गयी है।

तटीय सुरक्षा स्कीम के चरण-2 के तहत 131 तटीय पुलिस स्टेशनों, 180 नावों, 60 जेट्टियों, 10 बड़े पोतों (ए एंड एन), 131 चौपहिया वाहनों, 242 मोटर साइकिलों, 10 मेरिन ऑपरेशन सेंटरों और 35 रिजिड इनफ्लैटेबल नावों को शामिल किया गया है।